माननीय न्यायधीश टी.पी.एस. मान जी के समक्ष

रामेश्वर और अन्य, - अपीलकर्ता

बनाम

साधु और अन्य, - प्रतिवादी

आर.एस.ए. संख्या 1196, 2004

15 मई, 2008

सीमा अधिनियम, 1963-एस.5 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - दाखिल करने में लगभग 8 महीने की देरी दूसरी अपील - उस याचिका पर देरी की माफ़ी मांगी गई जो ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय पारित करने के बारे में नहीं जानती थी - क्या देरी की माफ़ी मांगने के लिए पर्याप्त कारण दिखाए गए - आयोजित, हाँ - पार्टियों के अधिकार गुण-दोष के आधार पर निर्धारित नहीं होते - अदालतों को बेहद उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले एक वादी द्वारा की गई देरी की माफ़ी की याचिका पर विचार करते समय - अपील की अनुमति दी गई, मामला प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेज दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि देश में रहने वाले अधिकांश लोग अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें कानून की जटिलताओं और अदालतों तथा न्यायाधिकरणों की कार्यवाही के बारे में भी जानकारी नहीं है। वे अपनी आजीविका कमाने में ही संतुष्ट रहते हैं और सभी के हाथों अन्याय सहते हैं। इन परिस्थितियों में, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले एक वादी द्वारा उठाए गए विलंब क्षमा की याचिका पर विचार करते समय न्यायालयों को अत्यंत उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि ऐसे मामलों में पुराने और पुरातन नियम को लागू किया जाता है कि प्रत्येक दिन की देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया जाना चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश आबादी के साथ गंभीर अन्याय होगा। अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्ति न्याय पाने के अपने वैध अधिकार से वंचित हो जाएंगे। (पैरा 10)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, कोई अपीलकर्ताओं को उक्त अपील दायर करने में देरी की माफी के मामले में उचित छूट देने के बाद निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपनी अपील को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित रूप से लाभ दे सकता है। , तो और अधिक। जब पार्टियों के अधिकारों को निचली अपीलीय अदालत द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है, इसके बजाय अपीलकर्ताओं को पहले चरण यानी अपील की स्वीकृति पर ही बाहर कर दिया गया है। साथ ही, वर्तमान दूसरी अपील में प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तरदाताओं को अपीलकर्ताओं के हाथों कार्यवाही को रोकने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जा सकता है क्योंकि बाद वाले इस न्यायालय से कब्जे के संबंध में यथास्थिति का आदेश प्राप्त करने में सक्षम थे। प्रस्ताव जारी होने के समय यानी 9 अप्रैल, 2004। (पैरा 14)

एस.एस. दीनारपुर, अपीलकर्ता के वकील।

अनिल क्षेत्रपाल, प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 और 21 से 23 के लिए वकील।

माननीय न्यायधीश टी.पी.एस. मान जी

(1) प्रतिवादी नंबर 1 ने, खेवट नंबर 138 मिनट खतौनी नंबर 369 मिनट वाली 26 कनाल की संपत्ति के बँटवारे के बाद विशिष्ट हिस्से पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। रेक्ट नंबर 70 खसरा नंबर

5/3 (2-0), 6(8-0), 7(8-0), 15(8-0), कित्तास 4 गांव घलौर, एच.बी. में स्थित है। संख्या 159 उप-तहसील रादौर, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर और परिणामस्वरूप प्रतिवादियों को उसके अंतिम विभाजन तक वाद भूमि के किसी भी विशिष्ट हिस्से पर निर्माण करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए।

(2) विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), जगाधरी ने 3 अक्टूबर 1996 के फैसले के तहत वाद संपत्ति के विशिष्ट हिस्से के कब्जे के लिए प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में मेट्स और सीमा द्वारा इसके विभाजन के बाद एक प्रारंभिक डिक्री पारित की। मुकदमे में प्रतिवादियों को उसके अंतिम विभाजन तक वाद भूमि के किसी भी विशिष्ट हिस्से पर कोई भी निर्माण करने से रोक दिया गया था। इसके बाद, अंतिम डिक्री की तैयारी के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा आवेदन दायर किया गया था। इस पर माया राम ने आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अलग बयान देकर इसे वापस ले लिया कि यदि अंतिम डिक्री स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार तैयार की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अंततः, 29 जनवरी, 2003 को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री तैयार करने का आदेश दिया।

(3) इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने 24 सितंबर, 2003 को जगाधरी में विद्वान जिला न्यायाधीश, यमुनानगर के समक्ष अपील दायर की। चूंकि अपील दायर करने में लगभग आठ महीने की देरी हुई थी, इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा एक आवेदन भी दायर किया गया था। विलंब क्षमा हेतु. यह आवेदन एक शपथ पत्र द्वारा विधिवत समर्थित था।

(4) निचली अपीलीय अदालत ने देरी की माफ़ी के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन पर विचार किया और माना कि अपीलकर्ता अपील दायर करने में देरी की माफ़ी के लिए पर्याप्त कारण तो दूर, कोई भी कारण बताने में बुरी तरह विफल रहे। . परिणामस्वरूप, आवेदन खारिज कर दिया गया। आवेदन ख़ारिज होने की स्थिति में अपील भी विचार हेतु टिक नहीं पाई और ख़ारिज कर दी गई। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय में वर्तमान दूसरी अपील दायर की।

(5) वर्तमान अपील में शामिल कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ताओं के पास लगभग आठ महीने की अवधि के बाद निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपील दायर करने में देरी की माफी मांगने के लिए कोई पर्याप्त कारण था।

(6) अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि स्थानीय आयुक्त ने मौके पर संपत्ति का सीमांकन नहीं किया और पिछले स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा डिक्री पारित की गई थी। अपीलकर्ताओं को पिछले स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के बारे में 17 सितंबर, 2003 को पता चला जब उत्तरदाताओं के पक्ष में कब्जे के वारंट जारी किए गए और हलका कानूनगो ने उसे निष्पादित करने के लिए मौके का दौरा किया। इसके अलावा, अपील दायर करने में देरी न तो जानबूझकर की गई थी और न ही विपरीत पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए देरी की रणनीति थी।

(7) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को 29 जनवरी, 2003 को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बारे में पूरी जानकारी थी, जब साधु और अन्य के आवेदन पर अंतिम डिक्री पारित की गई थी। इसलिए, वे अपील दायर करने में हुई देरी की माफ़ी मांगने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखा पाए।

(8) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया है।

(9) अपीलकर्ताओं द्वारा विद्वान निचली अपीलीय अदालत के समक्ष देरी की माफी मांगने का एकमात्र कारण यह था कि उन्हें 29 जनवरी, 2003 को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय पारित करने के बारे में पता नहीं था और उन्हें इसके बारे में पता चला। 17 सितंबर, 2003 को भी जब हल्का कानूनगो कब्जे के वारंट को निष्पादित करने के लिए मौके पर गए थे। प्रथम दृष्टया, अपीलकर्ताओं द्वारा स्थापित उपरोक्त संस्करण रिकॉर्ड से उपलब्ध नहीं है। विद्वान ट्रायल कोर्ट का निर्णय वर्तमान अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील की उपस्थिति में पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ताओं को निर्णय प्राप्त करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित माना गया। उन्होंने ऐसी कोई दलील नहीं दी है कि उन्हें उनके वकील द्वारा बिल्कुल भी सूचित नहीं किया गया था, जिन्होंने विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व किया था। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता कोई भी कारण स्थापित करने में सक्षम थे, पर्याप्त कारण तो दूर, जिससे अपील दायर करने में देरी की माफ़ी मांगी जा सके।

(10) हालाँकि, देश में रहने वाले अधिकांश लोग अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें कानून की जटिलताओं और अदालतों तथा न्यायाधिकरणों की कार्यवाही के बारे में भी जानकारी नहीं है। वे अपनी आजीविका कमाने में ही संतुष्ट रहते हैं और सभी के हाथों अन्याय सहते हैं। इन परिस्थितियों में, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले एक वादी द्वारा की गई देरी की माफी की याचिका पर विचार करते समय न्यायालयों को अत्यंत उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि ऐसे मामलों में पुराने और पुरातन नियम को लागू किया जाता है कि प्रत्येक दिन की देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया जाना चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश आबादी के साथ गंभीर अन्याय होगा। अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्ति न्याय पाने की अपनी वैध लड़ाई से वंचित हो जाएंगे।

(11) उपरोक्त दृश्य कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग बनाम एमएसटी कैटजी (1), से स्पष्ट रूप से वर्णित है। जिसमें यह माना गया कि न्यायालयों को देरी को माफ करने में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसे इस प्रकार देखा गया:-

> "विधानमंडल ने 1963 के भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को अधिनियमित करके देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान की है ताकि न्यायालयों को 'गुण-दोष' के आधार पर मामलों का निपटान करके पार्टियों को पर्याप्त न्याय करने में सक्षम बनाया जा सके। विधायिका द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" न्यायालयों को कानून को सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से लोचदार है जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है जो न्यायालयों की संस्था के अस्तित्व के लिए जीवन-उद्देश्य है। यह सामान्य ज्ञान है कि यह न्यायालय इस न्यायालय में शुरू किए गए मामलों में उचित रूप से उदार दृष्टिकोण अपना रहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह संदेश पदानुक्रम में अन्य सभी न्यायालयों तक पहुंचा है।

(1) एआईआर 1987 एस.सी. 1383

और इस तरह के उदार दृष्टिकोण को सिद्धांत रूप में अपनाया जाता है क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि:-

(1) आमतौर पर एक वादी को देर से अपील दायर करने से लाभ नहीं होता है।

(2) देरी को माफ करने से इनकार करने से एक सराहनीय मामला सामने ही खारिज हो सकता है और न्याय की हार हो सकती है। इसके विपरीत जब देरी को माफ कर दिया जाता है तो सबसे अधिक यह हो सकता है कि पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर कारण तय किया जाएगा।

(3) "हर दिन की देरी की व्याख्या की जानी चाहिए" का मतलब यह नहीं है कि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हर घंटे की देरी, हर सेकंड की देरी क्यों नहीं? सिद्धांत को तर्कसंगत सामान्य ज्ञान व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

(4) जब पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष गैर-जानबूझकर देरी के कारण किए जा रहे अन्याय में निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

(5) ऐसी कोई धारणा नहीं है कि देरी जानबूझकर, या दोषी लापरवाही के कारण, या दुर्भावना के कारण हुई है। देरी का सहारा लेने से वादी को कोई लाभ नहीं होता। वास्तव में वह एक गंभीर जोखिम उठाता है।

(6) यह समझना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की उसकी शक्ति के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।

इस परिप्रेक्ष्य से न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण बनाते हुए, अपील की स्थापना में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(12) इसी तरह का दृश्य एम.के. में प्रतिध्वनित हुआ। प्रसाद बनाम पी. अरुमुगम (2), जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर देरी की माफी में उदार दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। प्रासंगिक टिप्पणियों को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"सीमा अधिनियम की धारा 5 की व्याख्या करते समय, न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए धारा में विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास देरी को माफ करने या माफ करने से इनकार करने का विवेकाधिकार है, जैसा कि अनुभाग में प्रयुक्त "स्वीकार किया जा सकता है" शब्दों से स्पष्ट है। XXX XXX XXX XXX भले ही ऐसा लगता है कि अपीलकर्ता उतना सतर्क नहीं है जितना उसे होना चाहिए था, फिर भी उसका आचरण, कुल मिलाकर, उसे एक गैर-जिम्मेदार वादी के रूप में दंडित करने का औचित्य नहीं बनता है। उन्हें अधिक सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन इस तरह की अतिरिक्त सतर्कता अपनाने में उनकी विफलता को संपत्ति के संबंध में मुकदमेबाजी से बाहर करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, जिसे बेशक मूल्यवान माना जाता है।

(2) एआईआर 2001 एस.सी. 2497

एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के आवेदन पर निर्णय करते समय, न्यायालय को लागू फैसले, इसमें शामिल संपत्ति की सीमा और पार्टियों की हिस्सेदारी को ध्यान में रखना चाहिए था।''

(13) राम किशन एवं अन्य बनाम यू.पी. राज्य रोडवेज परिवहन निगम और अन्य (3), न्यायालय ने, भले ही अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कहानी को ठोस नहीं पाया, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया और मामले को वापस भेज दिया।

(14) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, अपीलकर्ताओं को मामले में उचित छूट देने के बाद निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपनी अपील को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित रूप से लाभ दिया जा सकता है। उक्त अपील दायर करने में देरी की माफ़ी, और भी अधिक, जब पार्टियों के अधिकारों को निचली अपीलीय अदालत द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है, इसके बजाय अपीलकर्ताओं को पहले चरण में ही बाहर कर दिया गया है, यानी अपील की स्वीकृति . साथ ही, वर्तमान दूसरी अपील में प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तरदाताओं को अपीलकर्ताओं के हाथों कार्यवाही को रोकने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जा सकता है क्योंकि बाद वाले इस न्यायालय से कब्जे के संबंध में यथास्थिति का आदेश प्राप्त करने में सक्षम थे। प्रस्ताव जारी होने के समय यानी 9 अप्रैल, 2004।

(15) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा अपील दायर करने में देरी माफ कर दी जाएगी। अपील को स्वीकार करने और स्वीकार किए जाने के छह महीने के भीतर उस पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ मामला निचली अपीलीय अदालत को भेज दिया गया है। अपीलकर्ताओं को रुपये का भुगतान करना होगा। प्रतिवादियों को लागत के रूप में 10,000 रु. दिए जाएंगे, जो इस न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिस्पर्धी उत्तरदाता बताए गए हैं।

(16) पार्टियां, अपने वकील के माध्यम से, आगे की कार्यवाही के लिए 21 जुलाई, 2008 को विद्वान निचली अपीलीय अदालत के समक्ष उपस्थित होंगी।

<u>अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा।</u>

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा.

(3) 1994 सप्लिमेंट। (2) एस.सी.सी. 507